

March 2022 Edition

Newsletter from Uttar Pradesh State Industrial Development Authority

In this edition...



**Foreword &
Milestones Achieved**



Key Updates



**Flagship Project
(Mega Food Park Baheri)**



**Investment
Opportunity
(Mega Food Park Baheri)**



**Investor Connect
(PepsiCo)**



E-Gov Initiatives



Way Forward



**Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA)
Towards Inclusive Sustainable Industrial Growth**

Foreword



Shri Arvind Kumar

**ACS, GoUP and
Chairman, UPSIDA**

“UPSIDA has facilitated grounding of investment of over INR 2,980 Crore in the previous year. This includes large players such as AB Mauri, PepsiCo, Amul, Air Liquide. The investment grounding was made possible on account of continuous efforts made by UPSIDA in ensuring responsive interventions (like OTS Scheme, integration of online services with Nivesh Mitra portal and other digital reforms) as per evolving requirement of its key stakeholders. We aim to continue with this momentum in helping the state attract investments and create employment opportunities with various investor friendly policies and ICT driven regulatory initiatives.”



**Shri Mayur
Maheshwari**

CEO, UPSIDA

“UPSIDA is committed to enhance the investor experience by ensuring transparent services delivered digitally, while reducing associated physical touch-points. In 2021, we launched OTS scheme with attractive incentives and opportunity for allottees to clear dues without need for physical visit. We have integrated many services with Nivesh Mitra portal, thus ensuring transparent and hassle-free investment process for our investors and allottees. Further, we have played an active role in enabling the pandemic response of GoUP by creating an oxygen grid of units spread over 18 districts. We will strive towards continuously improving the experience for all our stakeholders.”

Milestones

Inauguration of Amul plant in Varanasi by Hon'ble PM (23rd Dec 21)

Expected investment around INR 470 to 500 Crore and anticipated employment generation of 5,000 for youth of Kashi with direct benefit to farmers in terms of procurement linkage

Ground-breaking of Air Liquide plant in Mathura by Hon'ble CM (5th Jan 22)

Foreign investment of INR 360 Crore to produce 305 TPD of oxygen – this plant is expected to double the oxygen production capacity of the state

Launch of One Time Settlement Scheme

Valid till 31st Mar 2022 with attractive incentives. Unique reform measure by UPSIDA to help allottees clear their maintenance dues without physical visit to bank / UPSIDA office

UP demonstrated highest improvement in LEADS ranking

UP leapfrogged from 13th position (in 2019) to 6th position (in 2021). UPSIDA is the nodal agency for logistics & warehousing projects

Key Updates

On 23rd Dec 2021, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi laid down the foundation stone for Amul plant at Agro Park Karkhiyaon, Varanasi in the august presence of Hon'ble Chief Minister Shri Yogi Adityanath

UPSIDA's relentless efforts to promote white revolution in the State finally culminates successfully as Hon'ble Prime Minister lays the foundation stone of the upcoming unit of BANAS dairy in the auspicious presence of Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh at Agro Park, Varanasi



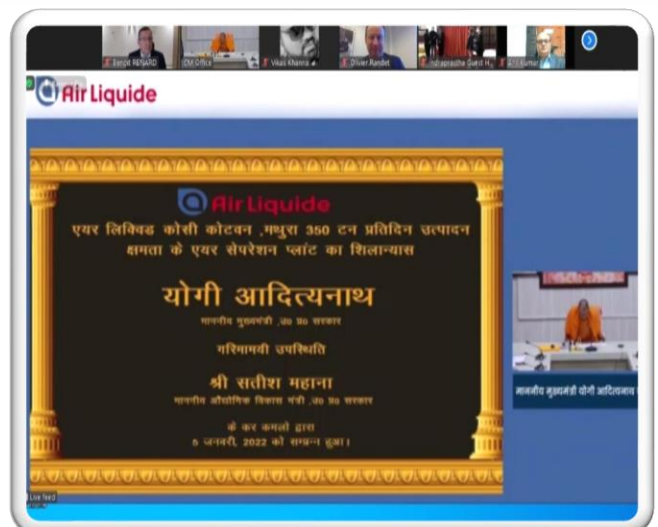
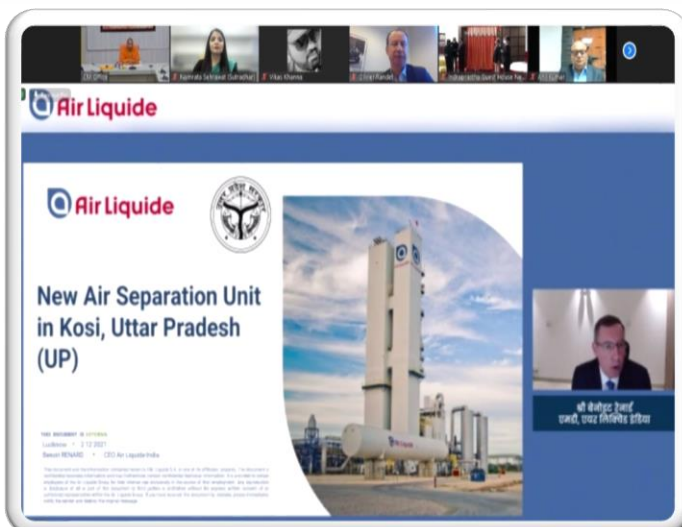
30 acres of land is allotted to Amul for its 3rd plant in UP. It is envisaged that around INR 470 to 500 Crores would be invested in this unit, which will generate direct and indirect employment of 5,000 and will have a capacity of processing 7.5 lakh Litres of milk per day. Setting up of this unit shall provide benefit to farmers in all the villages located within 50 km perimeter and shall also generate employment opportunity for the youth of Kashi.

Key Updates



On 5th Jan 2022, Groundbreaking of Air Liquide Oxygen plant in Mathura by Hon'ble Chief Minister Shri Yogi Adityanath

Air Liquide is setting up an oxygen plant at Kosi Kotwan, Mathura. Anticipated investment (foreign) is INR 360 Crores, and this plant is expected to manufacture 305 TPD of liquid & medical Oxygen along with liquid Nitrogen and liquid Argon. With this, oxygen production capacity of the state would be almost doubled – this would enable the state to respond to any emergency situations arising out of the pandemic



Key Updates



Launch of One Time Settlement (OTS) Scheme to help the allottees clear their maintenance dues without need for physical visits

To help its allottees and entrepreneurs clear their pending maintenance dues, UPSIDA launched OTS scheme on 20th Dec 2021. This scheme would be valid till Mar 31, 2022 and can be availed through Nivesh Mitra portal. While designing the OTS framework, UPSIDA has duly considered easy access to information and easy navigation option for its allottees and entrepreneurs.

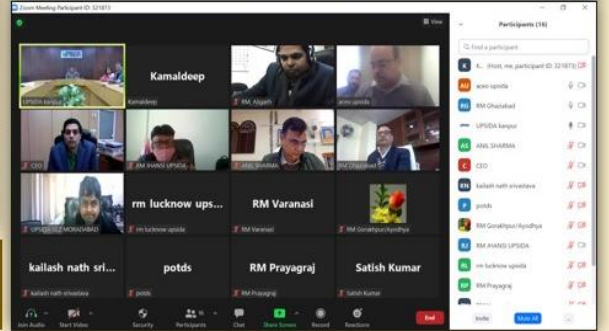


UPSIDA

Launch of One Time Settlement (OTS) Scheme for Maintenance Dues by UPSIDA CEO Shri Mayur Maheshwari

Date: 20th December, 2021
Time: 12:00 P.M.

LAUNCH OTS SCHEME



UPSIDA, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur, 208024 | Phone: 0512-2580906
Website: www.onlineupsidc.com | Email: md@upsidc.com

यूपीएसआइडी की ओटीएस योजना 20 से श्रांसी : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों के अनुरक्षण शुल्क एवं उस पर देय ब्याज की लंबित देनदारियों में सुविधा देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना 20 दिसम्बर से लागू की जायेगी। योजना के तहत उद्यमियों को बकाया भुगतान जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। छूट के उपरान्त देय धनराशि एकमुश्त या 25 प्रतिशत अप्रॉप्रेट भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जायेगी। यूपीएसआइडी की क्षेत्रीय प्रबन्धक गिरीश शर्मा ने बताया कि यह योजना 20 फरवरी तक लागू रहेगी। उद्यमियों को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी जायेगी। इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल <https://niveshmitra.up.nic.in> में ब्याज की बकाया राशि के विवरण में त्रुटि दिखने पर 10 फरवरी तक निराकरण की ऑनलाइन सुविधा भी दी जायेगी।

दिया है। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जारी की एकमुश्त समाधान योजना आधुनिक समाचार
कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक अनूठी पहल के अंतर्गत उद्यमियों के अनुरक्षण शुल्क और उस पर देय ब्याज की लंबित देयताओं की प्राप्ति तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।

भी प्रतियोगी ए लोक सरकार युवाओं का आ जुड़कर अपनी गारंटी हमारी चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में बार आम आद करेगी और आ मे हमारा किस आप लोगों के बहुमत में सरत व्यवस्था को म करते भी है। बिजली पानी के सांसद संज

बकाया मरम्मत शुल्क का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफ

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआइडी) के अध्यक्ष श्री मयूर महेश्वरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों के अनुरक्षण शुल्क एवं उस पर देय ब्याज की लंबित देयताओं को प्राप्ति तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के लंबित उच्चोत्तरण एवं अनुरक्षण में भी सहयोग मिलेगा। जो हर हाल में उद्यमियों और औद्योगिक मालिक के लिये बेहतर रहेगा। यह योजना 20 दिसम्बर से लागू की जा रही है। अगर योजना अर्वाधि में उद्यमों बकाया अनुरक्षण शुल्क जमा करते है तो उनको ब्याज पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। छूट के उपरान्त देय धनराशि को एकमुश्त अथवा 25 फीसदी अप्रॉप्रेट भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा मिलेगी। यह योजना दो माह के लिये अर्थात 20 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी। उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निवेश मित्र पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान को सुविधा भी रहेगी। उन्हें किसी भी कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं है।

कोविड से आई मंदी से उद्यमियों को उबारने की तैयारी
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों के अनुरक्षण शुल्क के भुगतान के लिए प्रथम बार 'एकमुश्त समाधान योजना' उपलब्ध कराई गई है। यह जानकारी यूपीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक केएम श्रीवास्तव ने मुंबई को दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ उद्यमियों के लिए प्राप्त होगा। इस योजना से न केवल कोविड-19 के कारण आई मंदी के प्रभाव से उद्यमियों को उबारने में बल्कि क्षेत्रीय अवस्थापना सुविधाओं के लंबित उच्चोत्तरण एवं अनुरक्षण में भी सहयोग होगा। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को बेहतर उद्योगपरक माहौल उपलब्ध होगा। एकमुश्त समाधान योजना 20 दिसंबर से शुरू की जा रही है। योजना अर्वाधि में उद्यमियों द्वारा अपने पूर्ण बकाया अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किए जाने की दृष्टि में भुगतान की तिथि तक उस पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। छूट के उपरान्त देय धनराशि को एकमुश्त अथवा 25 प्रतिशत भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान किए जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह योजना 20 फरवरी तक लागू रहेगी।

यूपीसीडा ने दी एकमुश्त समाधान योजना

कानपुर, 16 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण शुल्क भुगतान को लेकर पहली बार एकमुश्त समाधान योजना उपलब्ध करायी गयी है। प्राधिकरण उद्यमियों को अनुरक्षण शुल्क एवं उस पर देय ब्याज की लंबित देयताओं की प्राप्ति तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के लंबित उच्चोत्तरण एवं अनुरक्षण में भी सहयोग मिलेगा। जो हर हाल में उद्यमियों और औद्योगिक मालिक के लिये बेहतर रहेगा। यह योजना 20 दिसम्बर से लागू की जा रही है। अगर योजना अर्वाधि में उद्यमों बकाया अनुरक्षण शुल्क जमा करते है तो उनको ब्याज पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। छूट के उपरान्त देय धनराशि को एकमुश्त अथवा 25 फीसदी अप्रॉप्रेट भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा मिलेगी। यह योजना दो माह के लिये अर्थात 20 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी। उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निवेश मित्र पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान को सुविधा भी रहेगी। उन्हें किसी भी कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं है।



OTS scheme offers attractive incentives for payment of maintenance dues. Unique reform measure by UPSIDA to help its allottees clear their maintenance dues without physically visiting the bank branches / UPSIDA offices.

Key Updates



Warehousing and Logistics is a focus sector of the state and UPSIDA is the nodal agency for this sector



UP jumps 7 ranks in logistics improvement, Gujarat top performer in LEADS report



New Delhi, Nov 8 (UNI) The poll-bound state of Uttar Pradesh, which will test the five-year rule of Yogi Adityanath-led government in 2022, has leapfrogged 7 ranks since 2019, driven by policy initiatives, in a report on Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2021, unveiled by Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal on Monday.

States of Uttarakhand and Jharkhand have also witnessed a remarkable improvement in ranks compared to the 2019 LEADS ranking, emerging as top improvers.



लाजिस्टिक्स क्षेत्र में उप्र ने लगाई लंबी छलांग

राज्य की लंबी छलांग : करीब 7 रैंकों में सुधार के साथ देश के सभी राज्यों में दूसरे स्थान हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश ने अब लाजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार में लंबी छलांग लगाई है। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी लीड्स 2021 (लाजिस्टिक्स ईज अक्रॉस स्टेट्स) रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को छठवां स्थान हासिल हुआ है, जबकि वर्ष 2019 में यह तेरहवें पायदान पर था। इस तरह लाजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार और तरक्की कर उप्र ने सात पायदान की लंबी छलांग लगाई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल यह रिपोर्ट नहीं जारी की जा सकी थी।

असल में, प्रदेश सरकार की ओर से यूएई इंस्टिट्यूट ऑफ 2018 के दौरान इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति धारित की थी। नीति के तहत सॉफ्टवेयर, भूमि उपयोग और विकास शुल्क में छूट, स्टॉप शुल्क व इलेक्ट्रिसिटी इत्यादी में छूट कोशल विकास सॉफ्टवेयर सहित अनेक आकर्षक प्रोत्साहन दिए गए हैं।

इसके अलावा सरकार ने लाजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है व लाजिस्टिक्स में संचालन की लागत को कम करके उत्तर भारत में निवेश के लिए प्रदेशों में अनुकूल माहौल तैयार किया गया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री

पियूष गौतम की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की ओर से धिकारित की जा रही लाजिस्टिक्स सेवाओं के आधार पर उनका अंकन किया जाता है। तमना रिपोर्ट में गुजरात ने देश के 21 राज्यों में पहला स्थान बरकरार रखा है। लाजिस्टिक्स के तहत कारोबारी गतिविधियों को लागत को कम करने के उद्देश्य से अवस्थापना, संचार, भंडारण व परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाता है।

गौतम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट व सड़क परियोजनाओं को तेजी से विकसित करने में जुटी है।

LEADS Ranking 2021 – UP leapfrogged 7 positions (6th rank from 13th rank in 2019)



- As per Warehousing & Logistics Policy 2018, "industry status" granted to logistics sector
- Attractive fiscal incentives for the sector
- Multiple digital reforms and investor friendly approach by UPSIDA
- As on date, 8 approved logistics & warehousing projects spread over approx. 90 acres area with anticipated investment outlay of INR 463 Crores



Warehousing unit by Nanak Logistics Private Limited

Warehousing unit by Smt. Amrit Kaur

Key Updates



39th Board Meeting of UPSIDA took place on 2nd December 2021 chaired by Addl. Chief Secretary, Shri Arvind Kumar
Discussion took place on upcoming projects and reform measures to facilitate allottees and investors

39th Board Meeting of UPSIDA held today



UPSIDA, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur, 208024 | Phone: 0512-2580906

Website: www.onlineupsidc.com | Email: md@upsidc.com

@UPSIDAGoUP

@UPSIDA

UPSIDA sets up COVID helpdesk at industrial areas & regional offices and supports in creating state-level Oxygen grid



Overall, 34 Oxygen units spread across 18 districts of the state with an investment outlay of INR 576 Crore, out of which 19 units are operational and 8 units are under construction

Key Updates

“Mission Shakti” was observed in various industrial areas of UPSIDA to acknowledge the efforts of women entrepreneurs and stakeholders

Celebrating Mission Shakti with Entrepreneurs



UPSIDA, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur, 208024 | Phone: 0512-2580906

Website: www.onlineupsidc.com | Email: md@upsidc.com

 @UPSIDAGoUP

 @UPSIDA

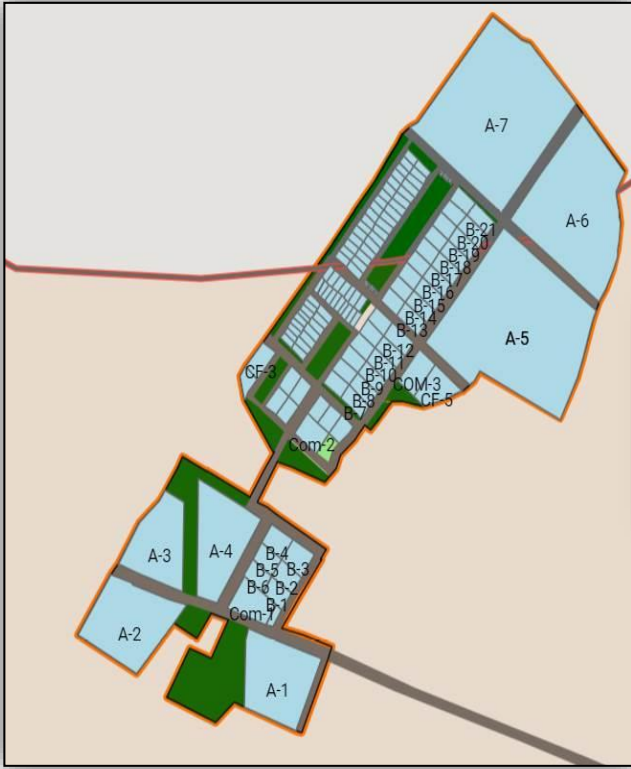
Mission Shakti event organized at Industrial Area Panki (31st Dec 2021)

CEO, UPSIDA Shri Mayur Maheshwari felicitated the Corona Warriors and Mission Shakti Champions during the program organised at GNEPIP, Surajpur Site V, GNOIDA



Mission Shakti event organized at GNEPIP Surajpur (24th Dec 2021)










Mega Food Park, Baheri, Bareilly District



246.15 acres
Total area including industrial land and support amenities

Land allotment has commenced for food processing industries



 <p>Infrastructure development almost complete (internal road network, boundary wall, streetlight, sanitation)</p>	 <p>Provision for utility services (electricity & dedicated substation & drinking water)</p>	 <p>Bareilly region is rich in agricultural resources (like rice, sugarcane)</p>
 <p>Located in the border of UP and Uttarakhand – location suitable for investors from Uttarakhand</p>	 <p>Rich agricultural resources and food process industrial ecosystem of UP and Uttarakhand – beneficial for investors</p>	 <p>Good access to multi-modal connectivity – seamless transport of raw materials & finished goods</p>
 <p>Forward and backward linkages with food processing industrial ecosystem in Bareilly</p>	 <p>Nivesh Mitra, Single Window System for online land allotment and other services available 24x7</p>	 <p>Availability of skilled and semi-skilled manpower in the region</p>



Uttar Pradesh State Industrial Development Authority

Inviting Food Processing Units

Mega Food Park, Baheri, District Bareilly



₹2,445 per sq. mt.
Location & Corner charges extra as applicable

*Industrial plots available for allotment from 30th November 2021

246.15 acre
For Food Processing Units

Industrial Plots of different sizes are available

600 sq.mt. 800 sq.mt. 1,000 sq.mt. 2,400 sq.mt. 3,400 sq.mt.

and bigger plots also available

Online Allotment through
Nivesh Mitra

<https://niveshmitra.up.nic.in/>

Development completed in Phase-1



55 km from Bareilly City & Airport

8 km from Baheri Tehsil

Well-connected with Nainital Road (SH-37)

10 km from Kichha railway station

250 km from Delhi Airport

Proximity to Uttarakhand – location suitability for investors from Uttarakhand

Benefits for Food Processing Industries

- Bareilly and immediate vicinity of Baheri known as major producer of agricultural, horticultural crops
- Prevalence of many food processing units in the region
- Hub of sugarcane production
- Close vicinity to rice producing belt of Tarai region
- Attractive incentives as per UP Food Processing Policy



Internal roads and support amenities



Rich agricultural resources in the region



Internal streetlights network



Good access to multimodal connectivity



33/11 KV Substation and electricity connection



Online services for pre and post investment support



Police Outpost proposed within the premises



Developed Infrastructure

For more details, please visit www.onlineupsidc.com or contact Regional Manager, Bareilly

+91 8707058688 Email: rmbareilly@upsidc.com

UPSIDA, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur - 208024 [@UPSIDAGoUP](https://www.facebook.com/UPSIDAGoUP) [@UPSIDA](https://twitter.com/UPSIDA)



PepiCo's largest greenfield investment in manufacturing in India

Inauguration of PepiCo plant in Mathura by Hon'ble CM; this plant is expected to ground INR 814 Crore investment and generate employment for 1,500 people with benefits to 5,000+ farmers



“The launch of our new plant in Kosi Kalan, Mathura is in line with the spirit of Atmanirbhar Bharat. Commissioning of the foods plant marks PepsiCo's single largest investment in the country. The support of the UP Government and local administration has been instrumental in commissioning of our state-of-the-art manufacturing facility in less than two years”

- Ahmed ElSheikh, President, PepsiCo India

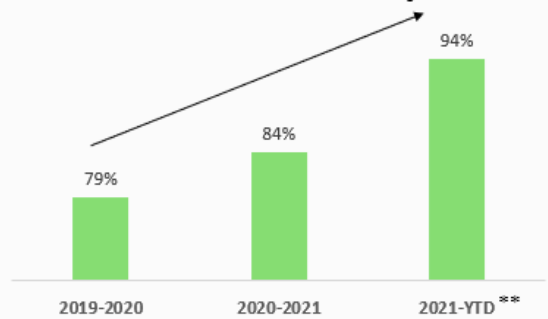
The success story of UPSIDA is attributed to digital led e-governance model Digital Transformation initiative by UPSIDA is aimed at providing online and transparent services to industry players across the life cycle of investment

Impact of digital-led initiative is evident from increasing no. of applications, reduction in physical visits, and rising user satisfaction levels



Provision of 24 e-governance/ online services which are also integrated with **Nivesh Mitra**

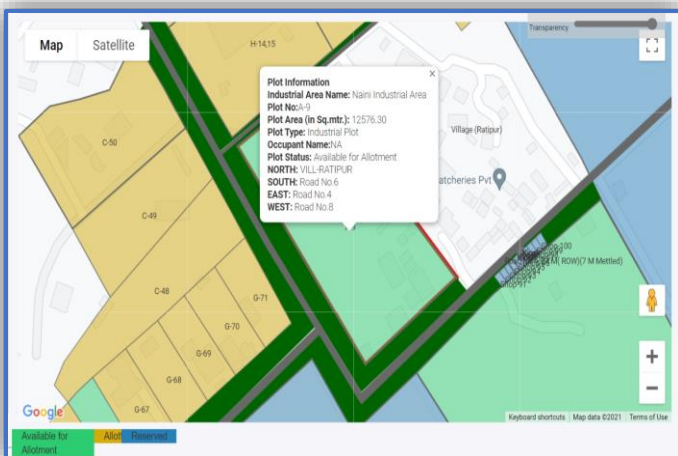
User satisfaction over the years



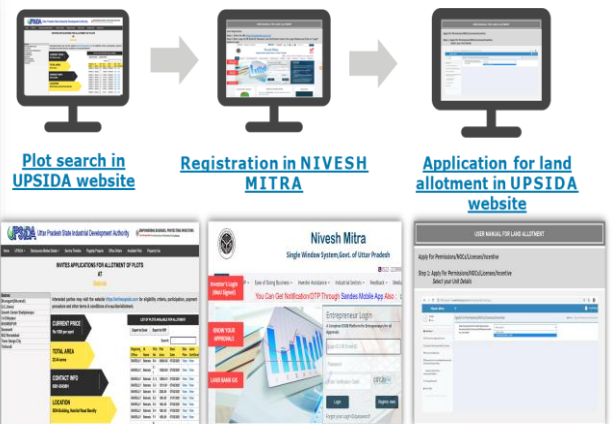
**YTD is till Jan 20, 2022

- Due to continuous digitization of existing processes, around **90%** of the applications were processed virtually, without any visit by the investor.
- The number of people asked to visit departments has decreased from **52% in FY 19-20 to 11% in FY 21-22 (YTD*)**
- Increase in Applications by **229% (CAGR) between FY 18-19 to FY 20-21** from the 15 Districts with lowest number of applications

GIS system captures detailed information of all 154 industrial areas and provides easy access to information for investors



Simplified & transparent land allotment process through Nivesh Mitra & UPSIDA portals



Way Forward



UPSIDA is committed to helping the State Government achieve its stated vision of becoming a \$ 1 tn economy by 2027

Interventions have been planned along the following key pillars



Key Projects

Key flagship projects which are aligned with state's priorities



Sustainable Industrial Areas

Adoption of national / international frameworks



Enabling Policy Framework

Ensuring investor responsiveness



Digitally-enabled Service Delivery

Transparent and time-bound services for enhanced ease of doing business



Internal Capacity development & Improvement

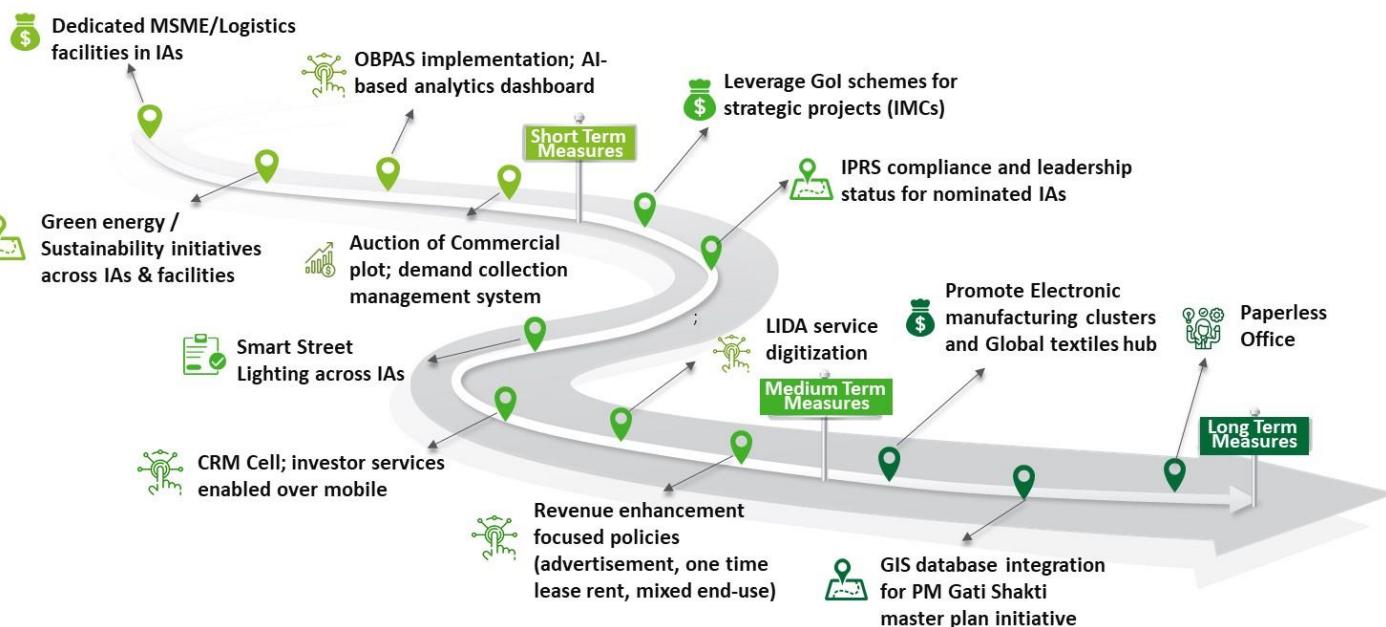
Reskilling / upskilling of UPSIDA officials



Financial self-sustainability

Surplus generation for making investments

Comprehensive road-map has been prepared to prioritize interventions in the short / medium / long term



IAs: Industrial Areas OBPAS: Online Building Plan Approval System; CRM: Customer Relationship Management; IPRS: Industrial Park Rating System
 LIDA: Lucknow Industrial Development Authority; IMC: Integrated Manufacturing Clusters; GoI: Government of India



**Committed to
making
Uttar Pradesh
shine on the
industrial map
of India**